

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2019—आषाढ़ 7, शक 1941

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 जून 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. (1987), अपर मुख्य सचिव, वन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से. (1987), अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त को केवल अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग तथा परिवहन आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
3. श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. (1991), प्रमुख सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
4. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग तथा परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
5. श्री त्रिलोक चंद महावर, भा.प्र.से. (2000), आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।  
 श्री त्रिलोक चंद महावर, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से सुश्री रीता शांडिल्य, भा.प्र.से. (2002), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, सहकारिता विभाग, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग केवल सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।
6. श्री भरत लाल बंजारे, भा.प्र.से. (2003), विशेष सचिव, वन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।
7. श्री अम्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), खनिज साधन विभाग के पद पदस्थ करते हुए संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।  
 श्री अम्बलगन पी., भा.प्र.से. द्वारा विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), खनिज साधन विभाग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल लाईन परियोजनाओं के कार्य हेतु), प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग को केवल प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।
8. श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से. (2004), विशेष सचिव, सहकारिता विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
9. श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (2005), संचालक, समाज कल्याण तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ निःशक्तजन, वित्त एवं विकास निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी के पद पर पदस्थ करता है।  
 श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
10. श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006), संचालक, आदिम जाति कल्याण तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम एवं वक्फ सर्वे आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।
11. श्री बसवराजू एस., भा.प्र.से. (2007), कलेक्टर, जिला-रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

12. श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, भा.प्र.से. (2007), संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
13. श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ करता है।
14. श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
15. श्री नीरज कुमार बंसोड़, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, आदिम जाति कल्याण के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक छ.ग. अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम एवं वक्फ सर्वे आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।  
  
श्री नीरज कुमार बंसोड़, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक, आदिम जाति कल्याण के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
16. श्री चंद्रकांत उईके, भा.प्र.से. (2008), संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर (आब.) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, समाज कल्याण के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ निःशक्तजन, वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
17. श्री डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोरिया के पद पर पदस्थ करता है।
18. श्री भोसकर विलास संदिपान, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 जून 2019

क्रमांक ई 1-13/2018/एक-2.— श्री भरत लाल बंजारे को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र. 727/2016 तथा 714/2016 में पारित आदेश दिनांक 25-04-2017 के परिपालन में दिनांक 04-01-2018 को रिव्यू डीपीसी आयोजित कर सलेक्ट लिस्ट-2010 के अंतर्गत भारत सरकार के अधिसूचना क्र. 14015/46/2017-एआईएस (I)-बी, दिनांक 06-04-2018 द्वारा भा.प्र.से. में नियुक्त करते हुए आदेश क्र. 14014/22/2004-एआईएस (I)-दिनांक 24-08-2018 द्वारा उन्हें भा.प्र.से. में 2003 बैच आबंटित किया गया है।

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में अनुषांगिक लाभ प्रदान करते हुए श्री भरत लाल बंजारे, भाप्रसे (2003) विशेष सचिव, वन विभाग को सेवा के अधिसमय वेतनमान (-Pay Matrix Level-14) में नियुक्त करता है।

3. श्री भरतलाल बंजारे को अधिसमय वेतनमान का लाभ वर्ष 2003 बैच के भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति तिथि से अर्थात् दिनांक 03-10-2018 से देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कमल प्रीत सिंह, सचिव.**

## कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 30 मई 2019

क्रमांक 2823/बी-4/21/2001/14-2.—राज्य शासन, एतद्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा-26 (2) के खण्ड (3) के उप खण्ड (चार, पांच एवं छः) में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करती है :—

1. श्री आनंद मिश्रा, शिवाजी चौक राजेन्द्र नगर बिलासपुर (चार) कृषि विकास के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला एक प्रख्यात उद्योगपति या विनिर्माता.
2. श्रीमती बल्लरी चन्द्राकर वार्ड-2, चन्द्राकर पारा, ग्राम मोखला, पो.आ. आरंग तह. आरंग, जिला-रायपुर.  
(पाँच)— ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्री.
3. श्री बोधराम कंवर, ग्राम हरदीबाजार, पो.आ.-हरदीबाजार, विकासखंड पाली जिला कोरबा.  
(छः) एक प्रगतिशील कृषक, अधिमान्यतः जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो.

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी दिनांक से 03 वर्ष से अनधिक होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 मई 2019

क्रमांक/3697/04/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	सिरलगढ़ प.ह.नं. 23	1.044	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.).	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 मई 2019

क्रमांक/3698/05/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बुटाकसा प.ह.नं. 23	0.275	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.).	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक/3699/06/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मोहड़ प.ह.नं. 23	0.635	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.).	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक/3700/07/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	आतरगांव प.ह.नं. 13	0.121	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.).	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक/3701/08/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मोहड़ प.ह.नं. 23	8.331	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.).	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जय प्रकाश मौर्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 12 जून 2019

क्रमांक 10136/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	डंगनिया प.ह.नं. 53	1.429	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-कोरबा.	रामपुर जलाशय योजनांतर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण कार्य के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**किरण कौशल**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 7 जून 2019

क्रमांक 1/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2019) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	संबलपुरी प.ह.नं. 14	3.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जून 2019

क्रमांक 04/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2019) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	खन्तहा प.ह.नं. 14	1.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर  
(1)  
रकबा  
(हेक्टेयर में)  
(2)

बिलासपुर, दिनांक 19 जून 2019

क्रमांक 2/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर  
(ख) तहसील-तखतपुर  
(ग) नगर/ग्राम-बेलमुण्डी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.190 हेक्टेयर

682	0.073
683/2	0.089
685	0.032
771/2	0.032
686	0.024
687/2	0.057
677	0.024
675	0.024
688/1	0.097
674/1,	
674/2,	
674/3,	0.020
674/4,	
674/5	
673/1,	
673/2,	
673/3,	0.049
673/4,	
673/5	
673/6	0.121



(1)	(2)	(1)	(2)
672	0.036	216	0.259
670	0.061	209/1	0.085
671/1	0.032	210/1	0.008
669	0.093	209/2	0.053
668	0.040	208/2	0.085
667/2	0.49	189/1	0.053
667/1	0.049	187/1	0.008
650/1	0.020	185/2,	0.040
658/1,	0.073	186	
658/4		190/1	0.109
658/3	0.089	205/2	0.073
658/2	0.065	228/1	0.008
656/1	0.020	710	0.105
624/2	0.069	706/2	0.275
625/2	0.069	250/21	0.162
627	0.053	192	0.045
628	0.020	204/2	0.057
422/1	0.073	198	0.012
421	0.113	195	0.004
372/6	0.049	194/1,	0.162
214/2	0.126	194/2	
372/7	0.109	194/3	0.016
214/1	0.008	422/2	0.032
366/21	0.049	374/15	0.109
366/1	0.040		
366/3	0.032	योग	91
366/24	0.053		5.190
366/9	0.040		
364/5	0.194	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.	
363	0.057		
187/2	0.077	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
361/1	0.049		
360/1	0.081		
359	0.065		
358/1	0.040		
16	0.073		
15	0.008		
482/14	0.085	बिलासपुर, दिनांक 19 जून 2019	
482/13	0.057		
232/1	0.085		
232/5	0.024		
233/1	0.028		
233/2	0.057		
232/3	0.036		
234/1	0.032		
233/3	0.036		
227	0.174		

क्रमांक 7/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		799	0.024
(क) जिला-बिलासपुर			
(ख) तहसील-तखतपुर		योग	35
(ग) नगर/ग्राम-मोछ			1.879
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.879 हेक्टेयर			
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.	
(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
666/2	0.020	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
650/4,	0.162	कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	
674		बलरामपुर, दिनांक 25 मार्च 2019	
675/2	0.040	क्रमांक 2138/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-	
675/1	0.053	अनुसूची	
733	0.045	(1) भूमि का वर्णन-	
734	0.045	(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज	
1291	0.012	(ख) तहसील-वाड्डफनगर	
739	0.057	(ग) नगर/ग्राम-सरना	
726/2	0.073	(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.26 हेक्टेयर	
743	0.073	खसरा नम्बर	
744	0.008	रकबा (हेक्टेयर में)	
750	0.024	(1)	
749	0.040	(2)	
748	0.073	225	
776	0.061	190	
775	0.057	177	
774	0.016	183	
773	0.061	214/3	
791/1,	0.105	0.30	
791/3		0.16	
793	0.081	0.11	
794	0.057	0.16	
795/1	0.162	0.31	
795/2	0.150		
812	0.012		
807	0.049		
806	0.040		
800	0.008		
802	0.045		
804/2	0.020		
803	0.117		
1289	0.089		

(1)	(2)
203	0.18
207/1	0.83
213	1.16
207/2	0.40
199	1.55
178	0.11
207/3	0.17
207/4	0.17
191	0.33
214/2	0.32
योग	15
	6.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरना कोईलीपारा मे सेमर जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्फनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हीरालाल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 13 जून 2019

क्रमांक/10186/भू-अर्जन/44 अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा
  - (ख) तहसील-कोरबा
  - (ग) नगर/ग्राम-कोरबा
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.266 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
881/1	0.234
882/1	0.032
योग	2
	0.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सर्वमंगला बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 25 फरवरी 2019

रा.प्र.क्र. 19/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-सूरजपुर
  - (ख) तहसील-सूरजपुर
  - (ग) नगर/ग्राम-पीढ़ा
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.19
4	0.01

(1)	(2)	अनुसूची	
7/1	0.06	(1) भूमि का वर्णन-	
37/1	0.15	(क) जिला-सूरजपुर	
36	0.10	(ख) तहसील-सूरजपुर	
39	0.08	(ग) नगर/ग्राम-नवगई	
40	0.08	(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.43 हेक्टेयर	
43	0.02	खसरा नम्बर	रकबा
46	0.01		(हेक्टेयर में)
52/1	0.20	(1)	(2)
53	0.03		
63	0.10		
65	0.08	233	0.08
66	0.06	234	0.02
316/2	0.21	235	0.07
316/3	0.29	232	0.01
317	0.12	237	0.13
318	0.22	238	0.02
319	0.05	251	0.03
323	0.03	242	0.06
326	0.08	267/2	0.05
37/2	0.01	274	0.03
		275	0.04
		461	0.08
		288/2	0.13
		430/1	0.07
		288/3	0.08
		430/5	0.08
		300	0.15
		304	0.05
		303	0.20
		427	0.20
		481	0.22
		423	0.11
		425	0.07
		426	0.12
		262/2	0.04
		276	0.30
		428	0.13
		430/2	0.07
		430/3	0.07
		430/4	0.08
		431/1	0.06
		431/2	0.11
		432	0.15
		433	0.05
		439	0.07
योग	2.18		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवगई व्यपवर्तन योजना जलाशय/परियोजना डूब क्षेत्र/नहर नाली निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.			
सूरजपुर, दिनांक 25 फरवरी 2019			
रा.प्र.क्र. 20/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—			

सूरजपुर, दिनांक 25 फरवरी 2019

रा.प्र.क्र. 20/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)	(2)	(1)	(2)
440	0.05	8/1	0.11
441	0.15	8/2	0.14
442	0.11	15/2	0.13
458	0.04	9	0.65
459	0.13	20	0.02
460	0.35	21	0.01
462/1	0.10	10	0.06
463	0.06	16	0.11
464	0.06	17	0.07
482	0.08	18	0.10
1325	0.06	19	0.09
		29	0.02
योग	4.43	30	0.01
		197	0.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवगई व्यपवर्तन योजना जलाशय/परियोजना डूब क्षेत्र/नहर नाली निर्माण हेतु.		193	0.12
		194	0.08
		195	0.08
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		196	0.17
		198	0.11
		236	0.08
		684	0.11
		685	0.31
		योग	2.96
सूरजपुर, दिनांक 25 फरवरी 2019			
रा.प्र.क्र. 21/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवगई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत जलाशय/परियोजना के डूब क्षेत्र/नहर नाली निर्माण हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-भरूआमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.05
7	0.24

सूरजपुर, दिनांक 25 फरवरी 2019

रा.प्र.क्र. 22/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		1888	0.032
(क) जिला-सूरजपुर		1887	0.112
(ख) तहसील-रामानुजनगर		1891	0.048
(ग) नगर/ग्राम-तेजपुर		1892	0.004
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.928 हेक्टेयर		1904	0.064
		1905	0.088
खसरा नम्बर	रकबा	1954	0.024
	(हेक्टेयर में)	1976	0.008
(1)	(2)	1900	0.004
		1908	0.012
10/2	0.036	1927	0.004
8/2	0.052	1958	0.020
7	0.112	1901/1	0.076
12	0.028	1959	0.024
14	0.068	1960	0.072
16	0.068	1950	0.056
22	0.040	1978	0.012
684	0.112	1940	0.120
19	0.088	1982/1	0.020
20	0.104	1984/2	0.044
678	0.128	1982/2	0.008
681	0.116	1984/1	0.044
692	0.076	1986	0.012
694	0.056	1987	0.060
695	0.088	1949	0.004
696	0.088	693	0.020
702/3	0.028	1901/2	0.012
712/4	0.028	1961/1	0.004
702/2	0.028	1977/1	0.004
712/3	0.024	1941/2	0.020
707	0.016	1941/3	0.032
702/1	0.028	1941/4	0.008
705/8	0.016	1941/5	0.020
706/1	0.024	1941/6	0.016
705/6	0.028	705/7	0.024
713/1	0.028		
712/2	0.032		
706/2	0.052	योग	2.928
706/2	0.052		
712/5	0.004	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुडघेला	
713/3	0.020	व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.	
1869	0.016	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
1868	0.120	(राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1867	0.044		

सूरजपुर, दिनांक 25 फरवरी 2019

(1)

(2)

रा.प्र.क्र. 23/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सूरजपुर  
(ख) तहसील-रामानुजनगर  
(ग) नगर/ग्राम-पण्डरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.964 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

587	0.044
586	0.032
530	0.064
534	0.040
99/1	0.096
92/1	0.092
505/2	0.044
536	0.024
88/2	0.012
89	0.004
86	0.032
87	0.068
83	0.004
84	0.032
505/3	0.012
564/2	0.008
535	0.064
529/1	0.116
91/2	0.028
93/1	0.064

546	0.084
-----	-------

योग	0.964
-----	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुडघेला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 25 फरवरी 2019

रा.प्र.क्र. 24/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सूरजपुर  
(ख) तहसील-रामानुजनगर  
(ग) नगर/ग्राम-पोंड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.908 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

20	0.064
14	0.004
15	0.056
16	0.052
42	0.084
50	0.040
52	0.060
54	0.004
55	0.032
77	0.124
104/1	0.008
67	0.068

(1)	(2)	(1)	(2)
70	0.052	831	0.048
74	0.116	788	0.052
71	0.004	838	0.040
78	0.040	773	0.048
79	0.032	777	0.020
80	0.004	778	0.008
103	0.020	843	0.072
134	0.008	331/2	0.004
137	0.088	263	0.008
138	0.044	842	0.004
140/1	0.048	277	0.008
772	0.060	846	0.072
805	0.056	279	0.012
829	0.040	267	0.020
132/1	0.040	274	0.104
221/3	0.052	273	0.016
133	0.064	266	0.152
126	0.032	229	0.012
127	0.016	258	0.032
129	0.036	249	0.052
130	0.056	259	0.024
132/3	0.004	222	0.100
125	0.048	220	0.132
128/2	0.004	32/1	0.032
184	0.064	32/2	0.060
185	0.032	296/2	0.024
288	0.128	296/1	0.016
292	0.100	774/1	0.010
321	0.084	774/2	0.006
325	0.080	250/1	0.036
285	0.024	776	0.004
286	0.024	834	0.004
290	0.004	835	0.004
291	0.040	836	0.004
326	0.120	837	0.008
319	0.020	840	0.032
320	0.072	250/2	0.044
276	0.040		
278	0.020	योग	3.908
280	0.028		
297	0.028	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुडघेला	
2208/287	0.004	व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.	
284	0.004		
822	0.016	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
826	0.028	(राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
827	0.020		
828	0.012	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
830	0.032	दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	



## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़  
इंद्रावती खण्ड, दारु कल्याण सिंह भवन के सामने, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2019

क्रमांक 259/स्था./2019/5987.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2, दिनांक 12-06-2019 के परिपेक्ष्य में डॉ. एस. भारती दासन, भा.प्र.से. को कलेक्टर, जिला-रायपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से आज दिनांक 13-06-2019 को पूर्वाह्न में भारमुक्त किया जाता है।

सुब्रत साहू,  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 2nd April 2019

No. 27/L.G./2019/II-2-4/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Registrar (I & E), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 09 days from 16-11-2018 to 24-11-2018 along with permission to leave headquarters from 16-11-2018 to 25-11-2018, earned leave for 19 days from 07-01-2019 to 25-01-2019 along with permission to leave headquarters from 07-01-2019 to 27-01-2019 and earned leave for 09 days from 11-02-2019 to 19-02-2019 along with permission to leave headquarters from 10-02-2019 to 19-02-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 287 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd April 2019

No. 28/L.G./2019/II-3-13/2008.—Shri Rajesh Kumar Shrivastava, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 02 days on 28-12-2018 & 29-12-2018b along with permission to leave headquarters, earned leave for 02 days on 24-01-2019 & 25-01-2019 earned leave for 03 days from 12-02-2019 to 14-02-2019 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 11-02-2019 till the night 11.00 p.m. of 14-02-2019 and commuted leave for 03 days from 18-02-2019 to 20-02-2019.

During the period of earned leave & commuted leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave & 413 days of half-pay leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd April 2019

No. 29/L.G./2019/II-2-14/2015.—Shri Sudhir Kumar, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 05 days from 18-02-2019 to 22-02-2019 along with permission to leave headquarters from 16-02-2019 to 22-02-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 166 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd April 2019

No. 30/L.G./2019/II-3-23/2010.—Shri Shailesh Kumar Tiwari, Judge, Family Court, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 09 days from 18-02-2019 to 26-02-2019 along with permission to remain out of headquarters after the court hours of 16-02-2019 till before the court house of 27-02-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd April 2019

No. 31/L.G./2019/II-3-35/2007.—Shri Ramashankar, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 04 days from 12-02-2019 to 15-02-2019 along with permission to remain out of headquarters from 12-02-2019 to 17-02-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ramashankar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd April 2019

No. 32/L.G./2019/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 06 days from 18-03-2019 to 23-03-2019 along with permission to remain out of headquarters from 16-03-2019 to 24-03-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 178 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,  
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN)

---